For Private Circulation Only



DEWAS UDYOG CIRCLE

Issue No – 435 Monthly Newsletter August, 2025

President

Mr. Ashok Khandelia **Hon. Secretary** Mr. Anjan Shah



Hindi Diwas



World Tourism Day

Norld Tourism Day

Inside pages.....

Knowledge Centre Notifications/Circulars Events Attainments Member's Corner Sponsor's Page

ASSOCIATION OF INDUSTRIES DEWAS

1/B, 1/B/2A,I. S.Gajra Industrial Area No. 1, A. B. Road, DEWAS (M.P.) Phone: (07272) 258052–53, 259455 E-mail: aidewas123@gmail.com Website: www.aidewas.org

KNOWLEDGE CENTRE

Hindi Diwas

Hindi Diwas (Hindi Day) is an annual event celebrated on September 14 in India to commemorate the adoption of Hindi as the official language of the Indian Union by the Constituent Assembly on this date in 1949. It was officially declared by the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, and is observed to promote and honor the Hindi language. The day also marks the birth anniversary of Beohar Rajendra Simha, a pivotal figure in the effort to establish Hindi as an official language.

World Tourism Day

Since 1980, the <u>United Nations World Tourism Organization</u> has celebrated **World Tourism Day** as <u>international observances</u> on <u>September 27</u>. This date was chosen as on that day in 1970, the Statutes of the UNWTO were adopted. The adoption of these Statutes is considered a milestone in global tourism. The purpose of this day is to <u>raise awareness</u> on the role of <u>tourism</u> within the international community and to demonstrate how it affects social, cultural, political and economic values worldwide.

At its Twelfth Session in <u>Istanbul</u>, <u>Turkey</u>, in October 1997, the UNWTO General Assembly decided to designate a host country each year to act as the Organization's partner in the celebration of World Tourism Day. At its Fifteenth Session in <u>Beijing</u>, <u>China</u>, in October 2003, the Assembly decided the following geographic order to be followed for World Tourism Day celebrations: 2006 in Europe; 2007 in South Asia; 2008 in the Americas; 2009 in Africa and 2011 in the Middle East.

Important Days in September				
September 5	Teacher's Day (Dr. Radhakrishnan's Birth Day)			
September 7	Forgiveness Day			
September 8	International Literacy Day Hindi day, World First Aid Day			
September 14				
September 16	World Ozone Day			
September 21	International Day of Peace/World Alzheimer's day			
September 25	Social Justice Day			
September 27	World Tourism Day			

"We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them." —Albert Einstein



संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर (म०प्र०)

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इन्दौर-452007 फोन नं.-0731-2533482 फेक्स-0731-2544264 ई-मेल dihsindore@gmail.com

कमांक 1271 / 2025

दिनांक 16.07.2025

।। परिपत्र ।।

विषय:- कारखाने में गठित सुरक्षा समिति की कार्यवाही बाबद्।

......00......

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41 के तहत म.प्र. कारखाना नियम, 1962 के नियम 73—(I) के अन्तर्गत सामान्यत 250 या उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले अथवा धारा 87 या 2(cb) के अन्तर्गत खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखाने में सुरक्षा समिति के गठन का प्रावधान है। सुरक्षा समिति द्वारा प्रति तिमाही या इससे कम अवधि में निरंतर बैठक की जाती है। इस समिति में कारखाना प्रबंधन व श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं। संपटी ऑफीसर और फैक्ट्री मेडिकल ऑफीसर भी इसके सदस्य होते हैं। प्रावधान अनुसार सुरक्षा समिति के कार्य और कर्त्तव्य निम्न है:—

- (क) अधिभोगी की "स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति" के ध्येय और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता और सलाह देना;
- (ख) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों को देखना और प्रस्तुत समस्याओं के व्यवहारिक हल तलाश करना;
- (ग) सभी कर्मकारों में सुरक्षा जागरूकता उत्पन्न करना;
- (घ) शैक्षणिक, प्रशिक्षण तथा प्रोन्नित संबंधी क्रियाकलापों को अंगीकार रिपोर्ट, आपात योजनाओं, सेफ्टी आडिट रिस्क असेसमेन्ट पर विचार—विमर्श करना और उन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को लागू करना;
- स्वास्थ्य और सुरक्षा का सर्वेक्षण करना और दुर्घटनाओं के कारणों का निर्धारण करना;
- (छ) कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति किसी संभावित आसन्न खतरे के बारे में की गई कोई शिकायत को देखना तथा सुधार के उपाय सुझाना; और
- (ज) इसके द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का पुनरावलोकन करना।

उक्त प्रावधानों के परिपालन में कारखाना प्रबंधन द्वारा नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों, व्यवस्थाओं पर निरंतर विचार कर श्रमिकों के हित में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न advisiory जारी की जाती है:—

(क) कारखाने के प्रत्येक श्रमिक इस हेतु प्रशिक्षित व प्रोत्साहित किया जावे कि वह कार्य स्थल पर उसके संझान में आने वाले प्रत्येक सम्भावित खतरे या जोखिम जैसे कि बाल—बाल बची हुई (Near miss) कोई छोटी सी मी दुर्घटना अथवा कारखाने में विद्यमान कोई असुरक्षित स्थितियों को तत्काल सुरक्षा समिति के समक्ष अथवा उसके सदस्यों के संझान में लाये।

1-Om

(का) ऐसी परिस्थितियाँ पर सुरक्षा समिति द्वारा गंभीरता से विचार कर उसके निराकरण हेतु व्यवस्था की जावे तथा इस पूर्ण कार्यवाही को सुरक्षा समिति के बैठक के कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जावे जिससे कि कारखाने में घटित होने वाली सम्मावित दुर्घटनाओं को कम अथवा समाप्त किया जा सके।

(ग) चोट रहित दिवस/दुर्घटना शून्य दिवस (Hurt Free Days) की जानकारी कारखाने में सहज दिखाई देने वाले सुविधाजनक स्थान पर सूधना पटल पर प्रदिश्ति की जाये। उक्त सुरक्षित प्रक्रियाओं के पालन से कारखानों में लगातार कितने दिनों तक चोट रहित दिवस/दुर्घटना शून्य दिवस (Hurt Free Days) बनाये रखने में कारखाना प्रबंधन को सफलता प्राप्त हुई है. इसकी जानकारी विभाग की दी जावे एवं निरीक्षण के समय भी दी जावे। किसी दुर्घटना के घटित होने या किसी ऐसे सुरक्षा प्रावधान का उल्लंधन पाये जाने पर जिसके कारण दुर्घटना की सम्भवना हो सकसी थी, को संभावित दुर्घटना (Hurt) माना जाए तथा पुनः (Hurt Free Day) की गणना शुन्य से आरंभ की जाये।

उक्त के आलोक में दुर्घटना घटित होने अथवा सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर विस्तृत आंतरिक परीक्षण कराया जावे एवं पाये गये कारणों को दूर करने के लिये आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जावे। इस सूचना से सभी श्रमिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाये रखने हेतु प्रोत्साहित होगे साथ ही स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर सजग भी होगे।

श्रमिकों की सुरक्षा के प्रति निरन्तर प्रतिबद्धता बनाये रखने हेतु जागरूकता लाने के लिए वर्ष में अन्य प्रभावी उपाय भी सुनिश्चित करें।

ऐसे कारखाने जिनमें सुरक्षा समिति के प्रावधान नियमानुसार लागू नहीं हो रहे हैं, वह भी यदि स्व स्फूर्ल होकर ऐसे ही व्यवस्था को अपनाये तो उन कारखानों में भी दुर्धटनाओं की संख्या शून्य हो सकती है। इसलिए श्रमिकों के तथा कारखानों के व्यापक हित में कारखानों का प्रबंधन इसी प्रणाली के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करें।

संचलिक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर (नंतप्रत)

प्रति.

. समस्त कारखाना अधिभोगी/प्रबंधक मध्यप्रदेश DEWAS UDYOG CIRCLE 05 August, 2025

NOTIFICATIONS/CIRCULARS





Hurt Free Days

As on Date

Last Incident Date



"Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible." —Tony Robbins

DEWAS UDYOG CIRCLE 06 August, 2025

NOTIFICATIONS/CIRCULARS

Ministry of Finance



Prime Minister Shri Narendra Modi, on the occasion of 79th Independence Day, highlights how Goods and Services Tax (GST) is a significant reform which has benefited the nation

To build an 'Atmanirbhar Bharat', the Central Government is proposing significant reforms in GST, focused on 3 pillars, of structural reforms, rate rationalisation, and ease of living

Key areas identified for next-generation reforms include rationalisation of tax rates to benefit all sections of society, especially the common man, women, students, middle class, and farmers

Reforms will also seek to reduce classification-related disputes, correcting inverted duty structures in specific sectors, ensuring greater rate stability, and further enhancing ease of doing business

GST reforms would strengthen key economic sectors, stimulate economic activity, and enable sectoral expansion

Posted On: 15 AUG 2025 10:51 AM by PIB Delhi

Prime Minister Shri Narendra Modi, on the occasion of 79th Independence Day, highlighted how Goods and Services Tax (GST), implemented in 2017, is a significant reform which has benefited the nation.

The Prime Minister underscored the importance of the next generation of reforms under GST, which brings relief to the common man, farmers, middle class and MSMEs.

To build an 'Atmanirbhar Bharat', the Central Government is proposing significant reforms in GST. It will be focused on 3 pillars, namely

- 1. structural reforms
- 2 rate rationalisation, and
- 3. ease of living

The Central Government has sent its proposal on GST rate rationalisation and reforms to the Group of Ministers (GoM) constituted by the GST Council to examine this issue.

Key areas identified for next-generation reforms include the rationalisation of tax rates to benefit all sections of society, especially the common man, women, students, middle class, and farmers.

Reforms will also seek to reduce classification-related disputes, correcting inverted duty structures in specific sectors, ensuring greater rate stability, and further enhancing ease of doing business. These measures would strengthen key economic sectors, stimulate economic activity, and enable sectoral expansion.

Key Pillars of the Centre's Proposed Reforms:

Pillar 1: Structural reforms:

- 1. Inverted duty structure correction: The correction of inverted duty structures to align input and output tax rates so that there is a reduction in the accumulation of input tax credit. This would support domestic value addition.
- 2 Resolving classification issues: Resolve classification issues to streamline rate structures, minimise disputes, simplify compliance processes, and ensure greater equity and consistency across sectors.
- 3 Stability and Predictability: Provide long-term clarity on rates and policy direction to build industry confidence and support better business planning.

Pillar 2: Rate Rationalisation:

- 1. Reduction of taxes on common-man items and aspirational goods: This would enhance affordability, boost consumption, and make essential and aspirational goods more accessible to a wider population.
- 2. Reduction of slabs: Essentially move towards simple tax with 2 slabs standard and merit. Special rates only for select few items.
- 3 Compensation Cess: The end of compensation cess has created fiscal space, providing greater flexibility to rationalise and align tax rates within the GST framework for long-term sustainability.

Pillar 3: Ease of Living:

- Registration: seamless, technology-driven, and time-bound, especially for small businesses and startups.
- 2 Return: Implement pre-filled returns, thus reducing manual intervention and eliminating mismatches.
- 3. Refund: faster and automated processing of refunds for exporters and those with inverted duty structure.

The Centre's proposal, anchored on the above three foundational pillars, has been shared with the GoM for further deliberations within the GoM. The Centre has taken this initiative with the aim of building a constructive, inclusive, and consensus-based dialogue among all stakeholders.

In the true spirit of cooperative federalism, the Centre remains committed to working closely with the States. It will be building a broad-based consensus with the States in the coming weeks, to implement the next generation of reforms as envisioned by Prime Minister Shri Narendra Modi.

The GST Council, when it meets next, will deliberate on the recommendations of GoM, and every effort will be made to facilitate early implementation so that the intended benefits are substantially realised within the current financial year.

The Government reaffirms its commitment to evolving the GST into a simple, stable, and transparent tax system — one that supports #InclusiveGrowth, strengthens formal economy and enhances Ease of Doing Business (EoDB) across the country.

Prime Minister Shri @narendramodi, on the occasion of 79th Independence Day, highlighted how Goods and Services Tax (GST), implemented in 2017, is a significant reform which has benefited the nation.

The Prime Minister underscored the importance of the next generation of reforms...

- Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 15, 2025

NB/KMN

(Release ID: 2156708) Read this release in: Gujarati , Assamese , Urdu , Hindi , Tamil , Telugu , Kannada

"We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them." —Albert Einstein

F.No. R-19025/27/2022-SS-I Government of India Ministry of Labour and Employment Social Security (SS-I) Division

> Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi. 21.08.2025

To,

The Director General, ESI Corporation, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi – 110002.

Subject: Forwarding of Notification for accepting alternate documents for identification of ESI beneficiaries -reg.

Sir.

I am directed to refer to ESIC's letter No. 11012/4/2025-BFT-II dated 20.06.2025 and to enclose herewith a copy of notification bearing no. S.O. 3792(E) dated 19.08.2025 regarding Aadhar authentication on voluntary basis and acceptance of alternate documents for identification of ESI beneficiaries for kind information and necessary action.

Encl: as above.

Yours faithfully,

Digitally signed by Dheerendra Mohan Khare Date: 21-08-2025 14:39:35 (D.M. Khare)

Under Secretary to the Government of India Tel: 23766903

926695/2025/59-1

रविस्टी सं. डी.एस.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265553 CG-DL-E-21082025-265553

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3688]

नई दिल्ली, मंगलबार, जगस्त 19, 2025/बावण 28, 1947

No. 3688]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2025/SHRAVANA 28, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

का.आ. 3792(अ).—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायिकी, लाभ और सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहलता की आवश्यकता को समाम करता है, प्रक्रियाओं को मरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईटीएआई) के साथ परामर्श के पश्चात, अपने दिनांक 15.12.2022 के पत्र संख्या 13(16)/2022-ईजी-II के अधीन श्रम और रोजगार मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मंत्रालय कहा गया है), भारत सरकार की यह अनुमति प्रदान की थी कि सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विहित उद्देश्यों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को प्रमाणीकरण करने और आधार मंख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और इसे आधार (वित्तीय और अन्य महायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन इसे अधिसुचित किया जा सकता है।

और, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन यथा विहित, मुशासन और सामाज कल्याण लाभों के अपव्यय की रोक्याम सुनिश्चित करने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त उद्देश्य कहा गया है) के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग हेतु आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन स्वैच्छित आधार पर होगा और कर्मचारी राज्य बीमा निगम केवल सदाशयी प्रमुविधा पाने वाले को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने साथ

5514 GI/2025

(1)

1

File No. R-19025/27/2022:55-1 (Compliter No. 139770)

Generated from eDffice by YOGESH KUMAR, ASO-(YK), ASSISTANT SECTION OFFICER, MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT on 31/08/2025 04:13 pm

Cont'd to next page

"Success is peace of mind, which is a direct result of self-satisfaction in knowing you made the effort to become the best of which you are capable." —John Wooden

926695/2025/55-1

2

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii)]

ही सुशासन और स्कीम तंत्र के प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए [जिसे इसमें इसके पश्चात उपयोग मामने कहा गया है] ही आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन करेगा।

अतः अब, श्रम और रोजगार मंत्रालय, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में और भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 230(अ), नारीख, 13 जनवरी, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 13 जनवरी, 2023 को प्रकाशित अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है, निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात: -

- (1) अधिनियम में यथा उपवंधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसमें प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।
 - (2) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पहचान के वैकल्पिक और ज्यवहार्य साधनों के बारे में आधार संख्या धारक को स्वित करेगा और आधार अधिप्रमाणित करने से मना करने या असमर्थ होने पर आधार संख्या धारक को किसी भी सेवा से मना नहीं करेगा, अर्थान:-
 - क, पामपोर्ट
 - ख. पैन काई
 - ग. ड्राइविंग लाइसेन्स
- यह अधिसुचना, शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. आर-19025/27/2022-एसएस-[]

डॉ महेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2025

S.O. 3792(E).— WHEREAS the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

AND WHEREAS, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. 13(16)/2022-EGII, dated 15.12.2022 to the Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the said Ministry), Government of India for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the Employees' State Insurance Corporation is allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, the Aadhaar authentication shall be performed for usage of digital platforms to ensure good governance and prevention of dissipation of social welfare benefits (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that Employees State Insurance Corporation shall perform the Aadhaar authentication only for delivery of social security benefits to bonn-fide beneficiaries as well as to ensure good governance and effective administration of scheme mechanism [hereinafter referred to as the use cases].

NOW, THEREFORE, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of subsection (4) of section 4 of the said Act and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Labour and Employment vide Number S.O. 230(E), dated the 13th January, 2023, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 13th January, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Ministry of Labour and Employment hereby notifies the following, namely:

 (1) The Employees' State Insurance Corporation, as provided in the said Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

2

File No. R-19025/27/2022-SS-I (Computer No. 139770)

Generated from eOffice by YOCESH KUMAR, ASO-(YK), ASSISTANT SECTION OFFICER, MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT on 21/08/2025 04:33 pm.

926695/2025/55-1

[भाग II—खब्ह 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

3

- (2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication shall be on voluntary basis. The Employees' State Insurance Corporation shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:-
- (a) Passport;
- (b) PAN card; and
- (c) Driving license.
- 2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. R-19025/27/2022-SS-I] Dr. MAHENDRA KUMAR, Jt Secy.

Uploaded by Dte, of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORROMA NATH
TADAVA

Option 110064

3

File No. R-19025/27/2022-SS-I (Computer No. 1)19770)

Generated from eOffice by YOGESH KUMAR, ASC-(YK), ASSISTANT SECTION OFFICER, MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT on 21/06/2025 04:39 pm

"It took me quite a long time to develop a voice, and now that I have it, I am not going to be silent." —Madeleine Albright



M.P. POWER MANAGEMENT COMPANY LIMITED M.P. POWEK IMATA OF TYPE CIN: U40109MP2006SGC018637 (A Government of MP Undertaking)

Regd. Office: Shakti Bhawan, Rampur Jabalpur Madhya Pradesh INDIA 482 008, Tel: 0761-2661111, Regd. Office: State Brawn, Kampar Januarya. Proposition of the Control of the Con

No. CGM (RM)/FPPAS/25-26/ /3 2_

To.

/Jabalpur/Dated 2 9 /08/2025

- 1. The Managing Director M.P. Paschim Kshetm VV Co. Ltd. G.P.H Compound, Polo Ground, Indore (M.P)
- 2. The Managing Director M.P. Madhya Kshetra VV Co. Ltd. Bijli Nagar Colony, Nishtha Parisar, Govindpura, Bhopal (M.P) 3.
- The Managing Director M.P. Poorv Kshetrn VV Co. Ltd. Block No.7 Ground Floor, Shakti Bhawan, Jabalpur (M.P)

Sub: - Fuel & Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) for the Month of Aug-2025.

First Amendment to MPERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) (1st Amendment) Regulation, 2021 (ARG-35(III) (i) of 2023)

As per the Regulations cited under reference, the FPPAS for the month of Aug-2025 has been calculated as 0.97 %.

Accordingly, the calculated FPPAS of 0.97 % is to be billed to the consumers on energy charge for one month commencing 24th Aug-2025. To comply with provisions of the Regulations, a detailed calculation sheet is attached herein for your reference and uploading the same on the website of the

Encl.: As above

Shailendrif Saxena Chief General Manager (RM) MPPMCL JABALPUR

Copy to: -

- OSD Energy, Deptt GoMP, Bhopal
- The Secretary, MPERC, Metro Plaza, Bittan Market, Arera Colony, Bhopal (2)
- (3) PS to MD. MPPMCL Jabaipur.
- (4) The Chief General Manager, Commercial (Conv.)/(Non-Conv.) MPPMCL
- Chief Financial Officer, MPPMCL, Jabalpur (6)
- Director (Commercial) / CGM (Commercial) MPPoKVVCL/MPMaKVVCL/MPPaKVVCL, Jabalpur/Bhopal/Indore-
- A copy of FPPAS calculation sheet is enclosed for uploading on the Company's website.

The CGM (IT) MPPMCL, Jabalpur-

A copy of FPPAS calculation sheet is enclosed for uploading on the Company's website.

Chief General Manager (Rovenue Management) : Block no. 12, Ground floor, Shakti Bhawan, Rampur, Jabalpur 482008, Telephone no. Offisei

Cont'd to next page

"I raise up my voice—not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. ... We cannot all succeed when half of us are held back." — Malala Yousafzai

Formula for Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge as per the Regulations, 2021 [ARG-35(III) (i) of 2021]".

Monthly FPPAS for
$$n^{th}$$
 Month (%) =
$$\frac{(A:H)+C}{= \frac{Distribution losses in \%}{100}}*100$$

Where,

- "Nth" Month means the month in which billing of fuel and power purchase adjustment surcharge component is done. This fuel and power purchase adjustment surcharge is due to changes in tariff for the power supplied in (n 2)th month;
- "A" Total units procured from all sources (n 2)th Month (in kWh) including Long-term, Medium-term and Short-term Power purchases (To be taken from the bills issued to Distribution Licensee);
- *B** Bulk sale of power out of total units procured (as per A) in (n 2)th Month (in kWh) = (to be taken from provisional accounts to be issued by State Load Dispatch Centre in each month);
- "C" Incremental Average Power Purchase Cost in Rs./kWh=D-E
- *D" Actual Average Power Purchase cost (PPC) for procurement of A-B units in (n 2)th Month (Rs./kWh) (computed)
- "E" Projected Average Power Purchase Cost (PPC) from all sources (Rs./kWh) (from Retail Supply Tariff Order of respective year).
- "Z" = [(Actual Power purchased from all the sources outside the State in (n 2)th Month (in kWh) * (1 Inter-state transmission losses in %/100) + Actual Power purchased from all the sources within the State (in kWh)) *(1 Intra-state losses in %/100) B] in kWh
- "ABR" = Average Billing Rate for the year (to be taken from the Tariff Order in ₹/kWh)
- "Distribution Loss (in %)" Normative Distribution Losses as given in table under Regulation 26.1
- "Inter-state transmission Losses (in %)" As per Tariff Order

FPPAS Computation as per the Formula Specified in First Amendment of MPERC MYT Regulations, 2021 dated 17th Feb 2023					
Sr.No.	Particulars		(N-2)th Month Jun-2		
1			Nth month	Aug-25	
-	Total Units procured in (n-2) month from all Sources	leWh	A	8,272,184,	
3	Bulk Sale of Power out of total units procured (As per A) in (n-2)th month Taken from provisional accounts issued by SLDC Net units	kWh	В	470,625,1	
	Contraction of the Contraction o	kwh	A-B	7,801,559,	
	Incremental Average Power Purchase Copt	Rs/kWh	С	0.06	
5	Distribution Loss as per the Turiff Order	96			
6	Z Factor			15.47	
7	ABIR as per the Tariff Order	RudeWh		7,407,573,	
8 N	Southly FPPAS for the Month of Aug-25 (%).		ABR	7.14	
29.0	7 ** Cons for the establish at Aug 25 (74)	76	((A-B)*C)*(Z*(1- Dist.%/100)*ABR())*100	0.97	
C	Incremental Average Power Purchase Cost	Ra/kWh			
9	Actual Average Power Purchase Cost for procurment of A-B units in (n-2)th Month-Computed	Rs/kWh	C-D-E	0.06	
		erange and	D	3.72	
	Projected Average Power Purchase Cost from All sources -As per Turiff Order	Rs./kWh	100	3.66	
D A	Actual Average Power Purchase Cost (Rs/KWh)		D= (Cust of A- Income		
11 /	Actual Power Purchase Cost for procurment of A	Rs	of B) / (A-B)	3.72	
	ncome from Power Sale of B	Rx	8	314185618	
13 II	neremental/Net Power Purchase Cont	Ra	ь	242971935	
14 P	rower procurement Quantum as per A	Kwh	(a-b)	289888424	
	ower Sale Quantum as per B	Kwh	A	827218428	
	let Units (A-B)	Kwh	B	470625151	
		E.VIII	(A-B)	780155912	
17 A	BR for the Year (Taken from Tariff Order for FY 26)	Rs./kWh		7.14	
S In	nter-state Transmission Losses us per TO FY 26	%		3.62	
z					
9 A	ctual Power Purchased from all sources outside the State in (n-2)th Month	1:Wh	5	7,407,573,55	
	ster-slate Transmission Lausen	76		5,051,216,9	
11 / 1/47	ower Purchased from all sources with in State		6	3.62	
	dra-state Transmission Losses	kWh	7	3,220,967,33	
	ower Sale Quantum as per B	96	Я	2.61	
		kWh	В	470,625,158	
	stribudon Laus as per the Tariff Croler FY 25	%	Avg	15.47	
E		96		17.00	
2 (0)	72	%		17.00	

EVENTS

TIRANGA YATRA

On the occasion of Independence Day, a rally of two-wheelers / cars was organized on August 14, 2025, Approx. 200 workers / employees from different Industries participated in this event.











"I raise up my voice—not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard.... We cannot all succeed when half of us are held back." — Malala Yousafzai

EVENTS

INTERACTION WITH COLLECTOR DEWAS AND EXECUTIVE DIRECTOR (MPIDC) UJIAIN

Shri Ritu Raj Singh, Collector Dewas, and Shri Rajesh Rathod, Executive Director - MPIDC, Ujjain visited the office of Association of Industries Dewas on 22nd August 2025 for having an interaction with our members.









"It took me quite a long time to develop a voice, and now that I have it, I am not going to be silent." — Madeleine Albright

DEWAS UDYOG CIRCLE 18 August, 2025

WITH BEST COMPLIMENTS FROM



SERVING THE DEWAS COMMUNITY SINCE 1962

GAJRA GEARS PRIVATE LIMITED

STATION ROAD

DEWAS (MP) - 455001, INDIA

PHONE: (91-7272)350400

E-mail: head.hr@gajra.com, Website:

www.gajra.com